

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
निशा गुप्ता

बनाम

उदय चंद गुप्ता

2018 का विविध अपील संख्या 5

25 अगस्त, 2023

(माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी ने प्रतिवादी-वादी-पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?

हेडनोट्स

यदि पत्नी की ओर से की गई कथित क्रूरता सच थी, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर करने के लिए नौ साल तक इंतजार क्यों किया। यह पति है, जिसे अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, जबकि पत्नी को पति की कोई चिंता नहीं है।
(अनुच्छेद 66, 68)

जहाँ तक इस आरोप का सवाल है कि पत्नी अपने पति को आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी देती थी, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और वैसे भी अगर किसी के खिलाफ कोई अपराध किया जाता है, तो पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार है - पति अपनी पत्नी को तब पीटता था जब वह दूसरी महिला के साथ उसके अवैध संबंध का विरोध करती थी। यहाँ तक कि पक्ष के बेटे ने भी गवाही दी है कि उसके पिता उसकी माँ को पीटते थे और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें बिजली का करंट भी लगाया था। कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की धमकी को क्रूरता नहीं माना जा सकता। यह पति का मामला नहीं है कि पत्नी झूठा आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी देती थी (अनुच्छेद 69)

जहाँ तक पत्नी द्वारा गेहूँ, चावल और अन्य अनाज, बर्तन और आभूषण बेचने के आरोप का संबंध है, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे भी, अनाज और अपने आभूषण बेचना क्रूरता नहीं माना जा सकता। (अनुच्छेद 70)

जहाँ तक इस आरोप का संबंध है कि पत्नी ने असामाजिक तत्वों की मदद से अपने पति को जान से मारने की धमकी दी, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पत्नी एक पर्दानशीन महिला है और जाहिर है कि उसका किसी असामाजिक तत्व या अपराधी से कोई संपर्क नहीं हो सकता। वैसे भी, उसके साक्ष्य में ऐसी धमकी की तारीख और स्थान के संदर्भ में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है। (अनुच्छेद 71)

जहाँ तक पति के इस आरोप का संबंध है कि वह कई बार बीमार पड़ा और क्लिनिक में भर्ती हुआ, लेकिन पत्नी कभी उसे देखने नहीं आई, इसका कोई सबूत नहीं है। पति ने अपनी बीमारी की तारीख और प्रकृति और अस्पताल में भर्ती होने के समय का कोई तर्क नहीं दिया है। उसने यह भी साबित नहीं किया है कि उसकी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में पता था और वह उससे मिलने नहीं आई। (अनुच्छेद 71)

पति, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि वह क्रूरता का आधार साबित करने में विफल रहा है। अपील स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद 73, 74)

न्याय दृष्टान्त

डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने, (1975) 2 एससीसी 326; शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, एआईआर 1988 एससी 121; ए. जयचंद्र बनाम अनिल कौर, (2005) 2 एससीसी 22; समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एससीसी 511; विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित, (2006) 3 एससीसी 778; रवि कुमार बनाम जुल्मी देवी, 2010 एससीसीआर 265; रामचंद्र बनाम अनंत, (2015) 11 एससीसी 539; गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य, (2002) 2 एससीसी 619; श्रीमती रीता निझावन बनाम श्री बाल कृष्ण निझावन, आईएलआर (1973) 1 दिल्ली 944; मोहनदास पणिक्कर बनाम दक्षिणायनी, 2013 एससीसी ऑनलाइन केर 24493;

हरभजन सिंह मोंगा बनाम अमरजीत कौर, 1985 एससीसी ऑनलाइन एमपी 8; श्रीमती उमा वंती बनाम अर्जन देव, 1995 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 56

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक; क्रूरता; मानसिक क्रूरता; हिंदू विवाह अधिनियम; पारिवारिक न्यायालय; वैवाहिक कलह; सबूत का मानक; पर्दानशी महिला; अंतरंगता और बेवफाई; जिरह; दुर्व्यवहार; परित्याग

प्रकरण से उत्पन्न

2008 बिहारशरीफ स्थित नालंदा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष तलाक मामला संख्या 72

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री सुदीश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री शशांक चंद्रा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मलिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का विविध अपील संख्या

=====

निशा गुप्ता, पिता- स्वर्गीय मथुरा प्रसाद, पति- श्री उदय चंद गुप्ता, निवासी मोहल्ला झिंग नगर,
थाना बिहार, जिला नालंदा।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

उदय चंद गुप्ता, पिता- गुरु प्रसाद साव, निवासी मोहल्ला झिंग नगर, थाना बिहार, जिला नालंदा।

... .. प्रतिवादी/वादी

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री सुदीप कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री शशांक चंद्र, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

दिनांक: 25-08-2023

वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें नालंदा स्थित पारिवारिक न्यायालय, बिहारशरीफ के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तलाक वाद संख्या 72/2008 में दिनांक 07.10.2017 को पारित निर्णय को

चुनौती दी गई है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 29.07.2008 को दायर याचिका, जिसमें पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करने के लिए तलाक की डिक्री की मांग की गई थी, को स्वीकार कर लिया गया है।

2. प्रतिवादी-वादी का मामला, दलीलों के अनुसार, यह है कि प्रतिवादी-वादी का विवाह अपीलकर्ता-प्रतिवादी के साथ 10 जुलाई, 1987 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह के बाद से, वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहे और वैवाहिक संबंध से दो पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र, नरेंद्र भारती का जन्म 16 मई, 1991 को और छोटे पुत्र, आदित्य कुमार का जन्म 15 अगस्त, 1998 को हुआ। आगे यह भी कहा गया है कि दूसरे पुत्र के जन्म के बाद, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया और वह हमेशा प्रतिवादी-वादी-पति की वृद्ध माँ से झगड़ा करती रहती थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि वह बिना किसी सूचना के अपने पति का घर छोड़कर चली जाती थी और जब पति या उसकी माँ पूछते थे, तो वह पति और उसकी माँ के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थी। वह खाना बनाने के लिए भी तैयार नहीं थी और उसने सब कुछ उसकी बूढ़ी माँ पर छोड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप पति का जीवन नर्क बन गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि 1999 से आज तक कोई सहवास नहीं हुआ, इसलिए पत्नी ने लगातार दस साल तक पति को छोड़ दिया। यह भी आरोप लगाया गया है कि 1999 से पत्नी पति के साथ क्रूरता से पेश आती थी, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है-

(i) पत्नी सारा सामान अलग से लेकर खाना बना रही थी और पति के लिए खाना बनाने को तैयार नहीं थी और हमेशा उससे झगड़ा करती थी, जिससे याचिकाकर्ता को घर की ऊपरी मंजिल पर अलग रहना पड़ा और पत्नी को एक-दूसरे से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए पति होटल में खाना खाने लगा। जब वह लगातार 4 और 5 महीने के लिए घर से बाहर गई, उस स्थिति में, प्रतिवादी-वादी अपने और अपने नाबालिग बेटों के लिए खाना बना रहा था, लेकिन जब पत्नी आई, तो उसने अपने बेटों को अपने पिता से बात न करने के लिए मजबूर किया और पत्नी के डर से, बेटे प्रतिवादी-वादी से बात करने की हिम्मत नहीं कर सके।

(ii) हालाँकि अपीलकर्ता-वादी अपने दोनों बेटों का भरण-पोषण कर रहा था, पत्नी हमेशा पति को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी देती थी और हमेशा झूठा मामला दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन जाती थी।

(iii) अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी ने पति की पीठ पीछे उसके खेतों से चावल, गेहूं और अन्य अनाज बेच दिए और साथ ही ₹60,000/- मूल्य के चांदी और पीतल के सभी महंगे बर्तन और शादी के अवसर पर पति द्वारा दिए गए सभी सोने और चांदी के गहने भी बेच दिए और जब प्रतिवादी-वादी कुछ कहता था, तो पत्नी उसे गालियाँ देती थी।

(iv) पत्नी ने असामाजिक तत्वों की मदद से पति को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए पति के लिए अपनी पत्नी के साथ रहना असंभव है।

(v) कई बार, पति गंभीर रूप से बीमार पड़ा और भाराओपर स्थित प्रशांत क्लिनिक में भर्ती हुआ, लेकिन पत्नी कभी उससे मिलने नहीं आई।

3. यह भी आरोप लगाया गया है कि पति ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दस साल बीत गए और पत्नी ने कभी परवाह नहीं की और न ही पति के साथ रहने को तैयार हुई। यह भी आरोप लगाया गया है कि पति ने इस मामले से पहले कोई वैवाहिक मामला दायर नहीं किया है।

4. नोटिस मिलने पर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज कराया। अपने लिखित बयान में, उसने अपनी शादी और वैवाहिक संबंध से दो पुत्रों को स्वीकार किया है। लेकिन उसने अपने खिलाफ लगाए गए अन्य सभी आरोपों से इनकार किया है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी-वादी एक बीमा व्यवसाय का एजेंट है और वह आरएसएस और भाजपा का एक सक्रिय सदस्य और उच्च पदस्थ भी है। परिणामस्वरूप, उसकी कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ घनिष्ठता हो गई, जिनमें से एक राजगीर की है और उसे उसका पति अक्सर अपने घर ले जाता था और उसके विरोध करने पर, उसका पति उसे पीटता था और इस रिश्ते के कारण, वह देर रात घर आता था और उसके प्रति उदासीन हो गया था और उसने उसमें रुचि लेना बंद कर

दिया था। हालाँकि, जब भी वह उसके पास आता था, वह उसका स्वागत करती थी और यह कहना गलत है कि पिछले दस वर्षों से कोई सहवास नहीं है। उसने आगे कहा कि वह उस महिला का नाम नहीं जानती जिसके साथ उसके पति के घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन वह उसका चेहरा जानती है और यह तलाक याचिका उससे शादी करने के इरादे से दायर की गई है। यह भी कहा गया है कि पति ने न केवल उसे, बल्कि अपने दो बेटों को भी छोड़ दिया है। वह न तो उनका सहयोग करता है, न ही उनकी शिक्षा का खर्च उठाता है और इसीलिए बड़े बेटे को इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भी दावा किया गया है कि जब भी उसका छोटा बेटा कपड़े और अन्य ज़रूरी सामान और कितारें माँगता था, तो वह उसे पीटता था। यह भी दावा किया गया है कि आरएसएस और भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में उसके राजनीतिक जीवन के कारण, स्थानीय पुलिस स्टेशन ने उसके साथ मिलीभगत की है और उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। उसने यह भी दावा किया है कि वह एक पर्दानशीन महिला है और वह बाहर नहीं जाती, इसलिए किसी भी असामाजिक तत्व के संपर्क में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और अपराधियों की मदद से अपने पति को मारने की कोशिश करने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता।

5. यह भी आरोप लगाया गया है कि वह हमेशा उसके साथ रहने को तैयार है और सच तो यह है कि पति खुद किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते उसे छोड़ने की बुरी नीयत रखता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसका पति उसे अलग-अलग तरीकों से परेशान करता था जैसे उसे पीटना, खाना और घरेलू सामान से वंचित करना और पड़ोसी महिला को उससे बात नहीं करने देना ताकि वह अकेला महसूस करे। यह भी आरोप लगाया गया है कि पति खुद घर की दूसरी मंजिल पर चला गया है और पत्नी और बेटों को उस मंजिल पर आने की अनुमति नहीं देता जहाँ वह रहता था और वह अक्सर घर से बाहर रहता है और जब भी आता है, देर रात को आता है और तब तक पत्नी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है और जब भी उसे नींद आने के कारण दरवाज़ा खोलने में देर हो जाती है, तो उसका पति उसे पीटता था। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब भी वह मंदिर में पूजा करने के लिए घर से बाहर जाती

है, तो पति तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और जब वह वापस आती है, तो वह देरी किये बिना दरवाजा नहीं खोलता। यह भी दावा किया गया है कि पति बीमा व्यवसाय से ₹12,000/- प्रति माह और उधार देने के व्यवसाय से ₹5,000/- प्रति माह कमीशन कमाता था। उसके पास पैतृक ज़मीन-जायदाद भी है, जिससे उसे खेती से प्रति वर्ष ₹2 लाख की आय होती है और इस आय के बावजूद, वह अपनी पत्नी और अपने बेटों का भरण-पोषण नहीं करता है।

6. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:

- “(i) क्या वाद स्वीकार्य है।
- (ii) क्या वादी के पास वाद दायर करने के लिए कोई कारण है।
- (iii) क्या प्रतिवादी वादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।
- (iv) क्या प्रतिवादी वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है।
- (v) क्या वादी तलाक की डिक्री का हकदार है।
- (vi) क्या वादी किसी अन्य राहत का हकदार है।”

7. प्रतिवादी/वादी ने मुकदमे के दौरान अपने वाद के समर्थन में निम्नलिखित पाँच गवाहों की जाँच की:

- i) अ.सा.-1- दिलीप कुमार सिंह, दिनांक 14.07.2009
- ii) अ.सा.- 2 – पारसनाथ, दिनांक 15.02.2010
- iii) अ.सा.- 3- परशुराम कुमार, दिनांक 24.02.2010
- (iv) अ.सा.- 4- विनोद कुमार, दिनांक 15.03.2010
- (v) अ.सा.- 5- उदय चंद गुसा, दिनांक 26.03.2010

8. दिलीप कुमार सिंह, जिनसे अ.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई है, दोनों पक्षों से परिचित हैं और हलफनामे के माध्यम से दायर अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने यह बयान दिया है कि प्रतिवादी-वादी की पत्नी गुस्सैल स्वभाव की है और वह अपने पति के साथ क्रूरता और उपेक्षा का व्यवहार करती है और वह अपने पति की बिना किसी सूचना या अनुमति के मायाके और अन्य स्थानों पर जाती थी। कभी-कभी, वह अपने छोटे बेटों को छोड़कर महीनों तक चली

जाती थी, जिससे उसके पति को कष्ट और मानसिक तनाव होता था। पति के पूछने पर, वह उसे गालियाँ देती थी। अपनी जिरह में, उसने यह गवाही दी है कि प्रतिवादी-पत्नी गुस्सैल स्वभाव की है। उसने यह भी गवाही दी है कि वह वादी/प्रतिवादी के घर 8 साल पहले गया था और वह कई बार उसके घर गया था। उसने आगे यह भी गवाही दी है कि पति एक अमीर आदमी है जिसके पास 10-12 बीघा ज़मीन है और वह एक बीमा एजेंट के रूप में भी काम करता है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने प्रतिवादी वादी की पत्नी के स्वभाव के बारे में झूठी गवाही दी है।

9. पारसनाथ, जिसकी अ.सा.- 2 के रूप में परीक्षा ली गई है, दोनों पक्षों से परिचित है और अपने मुख्य परीक्षा में हलफनामे के माध्यम से दायर की गई अपनी याचिका में वादी/प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया है कि वह उस मकान के मकान मालिक का नाम नहीं जानता जहाँ दोनों पक्ष रहते हैं। वह आस-पास के घरों में रहने वाले लोगों के नाम भी नहीं बता सकता। उसने इस बात से इनकार किया है कि दोनों पक्ष अपने-अपने घर में रहते हैं, किराए के घर में नहीं। वह बच्चों की शिक्षा के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। वह यह भी नहीं बता सकता कि दोनों पक्ष अलग-अलग रहते हैं या नहीं। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने झूठी गवाही दी है।

10. परशुराम कुमार- जिसकी अ.सा.- 3 के रूप में परीक्षा ली गई है, दोनों पक्षों से परिचित है और वह प्रतिवादी-पति का मित्र है और हलफनामे के माध्यम से दायर अपनी मुख्य परीक्षा में, उसने पति द्वारा तलाक की याचिका में दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उन्होंने यह बयान दिया है कि पति अपनी माँ से लगभग 10-12 वर्षों से अलग रह रहा है और उसकी माँ अपने दूसरे बेटे शिवरतन प्रसाद गुप्ता के साथ रह रही है। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि पक्षों का बड़ा बेटा मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद रांची में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह वर्तमान में कहाँ पढ़ रहा है। दोनों बेटे अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि प्रतिवादी/वादी वर्तमान में अपने घर से दूर रह रहा है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्हें नहीं पता कि वादी-पिता द्वारा खर्च का भुगतान न

करने के कारण बड़े बेटे की शिक्षा बाधित हुई है या नहीं। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने प्रतिवादी-निशा गुप्ता को गेहूँ, चावल आदि बेचते नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने वादी उदय चंद गुप्ता से यह बात सुनी है। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि 5 वर्षों से उदय चंद गुप्ता घर नहीं जा रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच पति-पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है।

11. विनोद कुमार, जिनसे अ.सा.- 4 के रूप में पूछताछ की गई है, दोनों पक्षों से परिचित हैं और वे वादी/प्रतिवादी के मित्र हैं और मुख्य परीक्षा में, हलफनामे के माध्यम से दायर, उन्होंने तलाक की याचिका में दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया है कि वादी/प्रतिवादी उनके मित्र हैं, हालाँकि वे रिश्तेदार नहीं हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वर्तमान में प्रतिवादी/वादी आरएसएस के कार्यालय में रह रहे हैं और वे वादी/प्रतिवादी के साथ आरएसएस के सदस्य हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बड़ा बेटा, नरेंद्र, जैसा कि उन्होंने सुना है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वे कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं और उन्हें वादी/प्रतिवादी ने निकाल दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि छोटा बेटा, आदित्य, रांची के करियर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका खर्च कौन उठाता है, लेकिन उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसका खर्च प्रतिवादी-पत्नी के माता-पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। उसने आगे यह भी बयान दिया है कि वादी/प्रतिवादी एक एलआईसी एजेंट है और उसकी मासिक आय 8-10 हजार रुपये है और वादी/प्रतिवादी के पास 5-7 बीघा ज़मीन-जायदाद भी है। उसकी जिरह में गवाहों द्वारा कोई अन्य महत्वपूर्ण बयान नहीं दिया गया है।

12. उदय चंद गुप्ता, जो स्वयं वादी/प्रतिवादी हैं, से अ.सा.- 5 के रूप में पूछताछ की गई है और अपने मुख्य परीक्षण में, जो हलफनामे के माध्यम से दायर किया गया है, उसने तलाक याचिका में दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उसने यह बयान दिया है कि पत्नी अभी भी उसके घर में रह रही है और उसका बड़ा बेटा नरेंद्र दिल्ली में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह किस विभाग में नौकरी कर रहा है। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उनका दूसरा बेटा आदित्य रांची के करियर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। उन्होंने यह भी

गवाही दी है कि वर्तमान में वह आरएसएस कार्यालय में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ नहीं रहते। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि वह एक एलआईसी एजेंट हैं, लेकिन उनका यह व्यवसाय समाप्त हो चुका है। हालाँकि, उन्हें पुरानी पॉलिसी से कमीशन के रूप में आय होती है। वह अपने भाइयों और माँ से बातचीत करते हैं। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि लगभग 10 वर्षों से उनकी अपनी पत्नी से बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि तलाक की याचिका दायर करने से पहले उनकी अपनी पत्नी से बातचीत होती थी और उनके साथ उनका वैवाहिक संबंध था और किराए के घर में जाने के बाद ही उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हुआ। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध है।

13. अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने मुकदमे के दौरान अपने बचाव के समर्थन में निम्नलिखित चार गवाहों से पूछताछ की है:

- i) व.सा.- 1 - निशा गुप्ता, दिनांक 12.05.2010
- ii) व.सा.-2 - सुरेश प्रसाद गुप्ता, दिनांक 28.07.2011
- iii) व.सा.-3 - अशोक कुमार, दिनांक 19.05.2012
- iv) व.सा. -4 - आदित्य कुमार, दिनांक 24.05.2012

14. निशा गुप्ता, जिनकी व.सा. -1 के रूप में पूछताछ की गई है, स्वयं प्रतिवादी/अपीलकर्ता हैं और हलफनामे के माध्यम से दायर मुख्य परीक्षा में, उन्होंने अपने लिखित बयान में दिए गए कथन को दोहराया है। अपनी जिरह में, उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि विवाह के बाद, उनके पति के साथ संबंध 2006 तक अच्छे थे और उसके बाद, पति द्वारा मारपीट किए जाने के कारण संबंध बिगड़ गए। हालाँकि, उसने गवाही दी है कि वह 2008 से अपने पति से अलग रह रही है। उसने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, लेकिन उसके पति के दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अदालत में कोई उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं कराया है। वह अपने ससुराल में रह रही है। उसका पति घर आता था, लेकिन वह कहाँ रहता है, यह उसे नहीं पता। एक बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है, दूसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और

उसकी पढ़ाई का खर्च उसके मायके के परिवार वाले उठा रहे हैं। वह उस महिला का नाम नहीं जानती जिसके साथ उसके पति का अंतरंग संबंध है, लेकिन वह उसे चेहरे से पहचान सकती है। वह राजगीर की उस महिला का नाम भी नहीं जानती जो उसके घर आती थी। वह अपने बच्चों के साथ अपने प्रतिवादी-पति के घर में रह रही है और उसका पति उसके साथ नहीं रहता। जब भी प्रतिवादी-पति उसे पीटता था, तो वह उसका इलाज करवाता था और वह यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ी सबूत दिखा सकती है कि उसके हाथ टूटे हुए थे। उसने पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया है, लेकिन अदालत में नहीं। उसने बयान के दौरान कोई अन्य महत्वपूर्ण बयान नहीं दिया है।

15. सुरेश प्रसाद गुप्ता, जिनसे व.सा. -2 के रूप में पूछताछ की गई है, दोनों पक्षों से परिचित हैं और प्रतिवादी-पत्नी के सगे भाई और वादी के बहनोई हैं और हलफनामे के माध्यम से दायर अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने लिखित बयान में दिए गए बयान को दोहराया है। वादी/प्रतिवादी को अवसर दिए जाने के बावजूद, उनसे जिरह नहीं की गई है।

16. अशोक कुमार, जिनसे व.सा. -3 के रूप में पूछताछ की गई है, दोनों पक्षों से परिचित हैं और हलफनामे के माध्यम से दायर अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने लिखित बयान में दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं दिया है।

17. लगभग 15 वर्षीय आदित्य कुमार से व.सा.-4 के रूप में पूछताछ की गई है, जो अपीलकर्ता और प्रतिवादी का पुत्र है और अपने मुख्य परीक्षण में, जो कि हलफनामे के रूप में दायर किया गया है, उसने अपनी माँ द्वारा लिखित बयान में दिए गए बयान को दोहराया है। अपनी जिरह में, उसने यह गवाही दी है कि 2006 से पहले, उसकी माँ और पिता के बीच संबंध अच्छे थे और उसके पिता अपने घर में रहते हैं, किराए के घर में नहीं। उसने यह भी गवाही दी है कि उसके पिता उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहते और वह उसे पीटते थे और यहाँ तक कि उसे बिजली का करंट भी लगाते थे। यह भी गवाही दी गई है कि उसकी माँ का खर्च उसका भाई उठाता है। इस गवाह ने ध्यान देने योग्य कोई अन्य महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है।

18. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंदी दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी/वादी की याचिका को स्वीकार करते हुए पाया कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी-पत्नी ने प्रतिवादी/वादी-पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था।

19. प्रतिवादी/अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा है और उसने गलत पाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी ने प्रतिवादी/वादी-पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, और प्रतिवादी/वादी-पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया। वह रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों का हवाला देते हैं और दलील देते हैं कि साक्ष्य के अनुसार, वास्तव में, प्रतिवादी/वादी-पति ने ही अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है और प्रतिवादी/वादी-पति, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं है। आलोचित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के साथ घोर अन्याय किया गया है। हालाँकि प्रतिवादी के विद्वान वकील विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आलोचना के निर्णय का समर्थन करते हैं।

20. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों के मद्देनजर, इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित दो बिंदु उठते हैं:

i) क्या अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी ने प्रतिवादी/वादी-पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है?

ii) क्या प्रतिवादी/वादी पति, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिक्री का हकदार है?

21. विचारणीय बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले, वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के भार और साक्ष्य के मानक के संबंध में केस लॉ या आधिकारिक न्यायिक घोषणाओं को देखना अनिवार्य है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने मामले में वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के भार की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की है,

जैसा कि 1975 (2) एससीसी 326 में रिपोर्ट किया गया है और इसमें निर्धारित कानून अभी भी लागू है। मामले के पैरा 23 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा है कि, निस्संदेह, अपना मामला साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर, भार उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य की पुष्टि करता है, न कि उस पक्ष पर जो उसे नकारता है। यह सिद्धांत सामान्य ज्ञान के अनुरूप है क्योंकि सकारात्मक को नकारात्मक की तुलना में साबित करना बहुत आसान है। इसलिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया है।

23. **सबूत के मानक** पर आते हुए, हम पाते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रतिवादियों के कदाचारों का वर्णन करने के लिए "वैवाहिक अपराध" शब्दों के प्रयोग के कारण कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए, डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने मामले में, जैसा कि 1975 (2) एससीसी 326 में बताया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ** के आधिकारिक निर्णय से पहले, परस्पर विरोधी विचार थे। एक दृष्टिकोण के अनुसार, वैवाहिक मामले सिविल प्रकृति के होते हैं और इसलिए ऐसे मामलों में प्रमाण का मानक प्रायिकताओं की प्रधानता होगी, जबकि दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम में "वैवाहिक अपराध" शब्द के प्रयोग को देखते हुए, वैवाहिक मामलों में उचित संदेह से परे प्रमाण प्रमाण का मानक होना चाहिए। हालाँकि, डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि वैवाहिक मामले सिविल प्रकृति के होते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक मामलों की सुनवाई में प्रायिकताओं की प्रधानता प्रमाण का मानक होगी, न कि उचित संदेह से परे प्रमाण, जो आपराधिक मुकदमों में लागू होता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (उपरोक्त) के पैरा 24 में कहा कि सिविल कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि किसी तथ्य को तभी स्थापित कहा जा सकता है जब वह प्रायिकताओं की प्रधानता से सिद्ध हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है जब न्यायालय या तो यह मानता है कि

वह मौजूद है या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह मौजूद है। इस प्रकार, किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास संभावनाओं के संतुलन पर आधारित हो सकता है। किसी तथ्य-स्थिति के संबंध में परस्पर विरोधी संभावनाओं का सामना करने वाला एक विवेकशील व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि तथ्य मौजूद है, यदि विभिन्न संभावनाओं को तौलने पर वह पाता है कि प्रबलता उस विशेष तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में है। एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में, न्यायालय यह पता लगाने के लिए इस परीक्षण का उपयोग करता है कि क्या किसी विवादित तथ्य को सिद्ध कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में पहला चरण संभावनाओं को निश्चित करना है, दूसरा उन्हें तौलना है, हालाँकि दोनों अक्सर आपस में मिल सकते हैं। असंभव को पहले चरण में और असंभाव्य को दूसरे चरण में हटा दिया जाता है। संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला में, न्यायालय को अक्सर एक कठिन चुनाव करना पड़ता है, लेकिन यही चुनाव अंततः यह निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रबलता कहाँ है। लेकिन चाहे मामला क्रूरता का हो या प्रोनोट पर ऋण का, लागू होने वाला परीक्षण यह है कि क्या संबंधित तथ्य संभावनाओं की प्रबलता पर सिद्ध होता है। सिविल मामलों में, सामान्यतः, यह प्रमाण का मानक होता है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या सबूत का भार मुक्त हुआ है।

24. वैवाहिक मामलों में "उचित संदेह से परे प्रमाण" के प्रयोग को खारिज करते हुए, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. नारायण गणेश दास्ताने** मामले के पैरा 25 में (उपरोक्त) यह टिप्पणी की है कि उचित संदेह से परे प्रमाण एक उच्चतर मानक द्वारा प्रमाण है जो सामान्यतः आपराधिक मुकदमों या अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मुद्दों की जाँच से संबंधित मुकदमों को नियंत्रित करता है। एक आपराधिक मुकदमे में विषय की स्वतंत्रता शामिल होती है, जिसे केवल संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर नहीं छीना जा सकता। यदि संभावनाएँ इतनी अच्छी तरह से संतुलित हैं कि एक उचित, न कि एक अस्थिर, मन यह पता नहीं लगा पाता कि प्रधानता कहाँ है, तो सिद्ध किए जाने वाले तथ्य के अस्तित्व के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और ऐसे उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है। विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति के मुकदमों में ऐसे

विचारों को शामिल करना गलत है। डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (उपरोक्त) के पैरा 26 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। धारा 23 न्यायालय को डिफ्री पारित करने की शक्ति प्रदान करती है यदि वह अपनी उप-धारा (1) के खंड (क) से (ड) में उल्लिखित मामलों पर "संतुष्ट" है। यह देखते हुए कि अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति की है, "संतुष्ट" शब्द का अर्थ "संभावनाओं की अधिकता पर संतुष्ट" होना चाहिए, न कि "उचित संदेह से परे संतुष्ट"। धारा 23 सिविल मामलों में सबूत के मानक में कोई बदलाव नहीं करती है।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (उपरोक्त) के पैरा 27 में आगे कहा है कि वैवाहिक मामलों में सबूत के मानक के बारे में गलत धारणा शायद ऐसे मामलों में प्रतिवादी के आचरण के बारे में एक ढीले-ढाले विवरण से उत्पन्न होती है, जो उसे "वैवाहिक अपराध" बनाता है। जीवनसाथी के ऐसे कृत्य जो वैवाहिक बंधन की अखंडता को नुकसान पहुँचाने के लिए किए जाते हैं, उनका सामाजिक महत्व होता है। विवाह करना या न करना और यदि करना है तो किससे, यह एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन वैवाहिक बंधन तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं। विवाह संस्था में समाज की हिस्सेदारी है और इसलिए गलती करने वाले जीवनसाथी को केवल एक चूककर्ता नहीं, बल्कि एक अपराधी माना जाता है। लेकिन यह सामाजिक दर्शन, हालाँकि किसी आरोप को विवाह विच्छेद के आधार के रूप में स्वीकार करने से पहले उसके स्पष्टतम प्रमाण की आवश्यकता पर प्रभाव डाल सकता है, वैवाहिक मामलों में प्रमाण के मानक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी एआईआर 1988 एससी 121 में रिपोर्ट के पैरा 10 के अनुसार यह भी टिप्पणी की है कि यह देखते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक सिविल प्रकृति की है, शब्द 'संतुष्ट' का अर्थ 'संभावनाओं की अधिकता पर संतुष्ट' होना चाहिए, न कि 'उचित संदेह से परे संतुष्ट'। अधिनियम की धारा 23 सिविल मामलों में सबूत के मानक को नहीं बदलती है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर के पैरा 10 में, जैसा कि 2005(2) एससीसी 22 में रिपोर्ट किया गया है, यह टिप्पणी की है कि विवाह जैसे नाजुक मानवीय रिश्ते में, मामले की संभावनाओं को देखना आवश्यक है। संदेह की छाया से परे सबूत की अवधारणा को आपराधिक मुकदमों पर लागू किया जाना चाहिए, न कि सिविल मामलों पर और निश्चित रूप से पति-पत्नी जैसे नाजुक व्यक्तिगत संबंधों के मामलों पर नहीं। इसलिए, किसी मामले में क्या संभावनाएँ हैं, यह देखना होगा और कानूनी क्रूरता का पता लगाना होगा, केवल तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष के कार्यों या चूक के कारण शिकायतकर्ता पति/पत्नी के मन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में। क्रूरता शारीरिक, भौतिक या मानसिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में, ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक क्रूरता के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं भी हो सकते हैं। जिन मामलों में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अदालतों को मानसिक प्रक्रिया और साक्ष्य में सामने आई घटनाओं के मानसिक प्रभाव की जाँच करनी होती है। इसी दृष्टिकोण से वैवाहिक विवादों में साक्ष्य पर विचार करना होगा।

28. माननीय केरल उच्च न्यायालय ने, ए. जयचंद्र मामले (उपरोक्त) का हवाला देते हुए, मोहनदास पणिकर बनाम दक्षिणायनी मामले के पैरा 19 में, जैसा कि 2013 एससीसी ऑनलाइन केर 24993 में रिपोर्ट किया गया है, यह टिप्पणी की है कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि दीवानी मामलों में, संभावनाओं की प्रबलता मामले को साबित करने के लिए अपनाया जाने वाला मानक है। निःसंदेह, वैवाहिक मामले दीवानी कार्यवाही हैं और न्यायालय संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर कार्य कर सकता है, विशेष रूप से व्यभिचार के मामलों में, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है।

29. अब आइए उन बिंदुओं पर विचार करें जो विचारार्थ तैयार किए गए हैं।

बिंदु संख्या 1

30. यह विचार करने से पहले कि क्या प्रतिवादी/पत्नी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध क्रूरता की है या नहीं, यह देखना अनिवार्य होगा कि इस विषय पर वैधानिक प्रावधान और केस कानून क्या हैं।

31. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई-ए) के तहत क्रूरता को तलाक के आधारों में से एक माना गया है। प्रावधानों के अनुसार, यदि दूसरे पक्ष ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, तो किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है।

32. हालाँकि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई-ए) में प्रयुक्त 'क्रूरता' शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इस शब्द की व्याख्या **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा कई अवसरों पर की गई है।

33. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने, **शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी** के पैरा 4 में, जैसा कि **एआईआर 1988 एससी 121** में रिपोर्ट किया गया है, यह टिप्पणी की है कि 'क्रूरता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। इसका प्रयोग मानव आचरण या मानवीय व्यवहार के संबंध में किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में किया गया आचरण है। यह एक व्यक्ति का आचरण है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। अगर यह शारीरिक है तो अदालत को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और उसकी मात्रा का प्रश्न है। अगर यह मानसिक है तो समस्या कठिन हो जाती है। सबसे पहले, जाँच क्रूर व्यवहार की प्रकृति से शुरू होनी चाहिए। दूसरा, इस व्यवहार का पति/पत्नी के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या इससे यह उचित आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा। अंततः, यह आचरण की प्रकृति और शिकायतकर्ता पति/पत्नी पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालने का विषय है। हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ शिकायत किया गया आचरण अपने आप में काफी बुरा और अपने आप में अवैध या गैरकानूनी हो। तब दूसरे पति/पत्नी पर प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जाँच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, क्रूरता तभी स्थापित होगी जब आचरण स्वयं सिद्ध या स्वीकार किया जाएगा।

34. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शोभा रानी मामले** (उपरोक्त) के पैरा 5 में आगे कहा है कि यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि हमारे आस-पास के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विशेषकर वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में, हम एक बड़ा बदलाव देखते हैं। ये घर-घर या व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग स्तर के होते हैं। इसलिए, जब कोई पति या पत्नी अपने जीवनसाथी या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के व्यवहार की शिकायत करता है, तो न्यायालय को जीवन के मानक की तलाश नहीं करनी चाहिए। एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक समूह दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पक्षकार किस प्रकार के जीवन के आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर कर सकती है जिन्हें वे महत्व देते हैं। इसलिए, न्यायाधीशों और वकीलों को जीवन के बारे में अपनी धारणाओं को लागू नहीं करना चाहिए। वे उनके साथ समानांतर नहीं चल सकते। उनके और पक्षों के बीच एक पीढ़ी का अंतर हो सकता है। बेहतर होगा कि वे अपने रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों को अलग रखें। यह भी बेहतर होगा कि वे मिसालों पर कम निर्भर रहें। हर मामला अलग हो सकता है। ये मामले ऐसे मनुष्यों के आचरण से संबंधित हैं जो आम तौर पर एक जैसे नहीं होते। मनुष्यों में क्रूरता के प्रकार की कोई सीमा नहीं है। किसी भी मामले में नए प्रकार की क्रूरता सामने आ सकती है, जो मानवीय व्यवहार, शिकायत किए गए आचरण को सहन करने की क्षमता या अक्षमता पर निर्भर करती है। क्रूरता का दायरा ऐसा ही अद्भुत है।

35. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शोभा रानी मामले** (उपरोक्त) के पैरा 17 में यह भी कहा है कि जिस संदर्भ और व्यवस्था में इस धारा में 'क्रूरता' शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रूरता में इरादा एक आवश्यक तत्व नहीं है। इस शब्द को वैवाहिक मामलों में इस शब्द के सामान्य अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। यदि शिकायत किए गए आचरण या क्रूर कार्य की प्रकृति से नुकसान पहुँचाने, परेशान करने या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है, तो क्रूरता आसानी से स्थापित की जा सकती है। लेकिन इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यदि मानवीय मामलों

में सामान्य समझ से, शिकायत किए गए कार्य को अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। पक्ष को राहत इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि कोई जानबूझकर या जानबूझकर दुर्यवहार नहीं किया गया है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य**, जैसा कि 2002(2) एससीसी 619 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि क्रूरता की अवधारणा और उसका प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है, और यह उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त धारा के तहत अपराध गठित करने के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। किसी मामले में मानसिक यातना या असामान्य व्यवहार भी क्रूरता और उत्पीड़न माना जा सकता है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर** के पैरा 10 में, जैसा कि 2005(2) एससीसी 22 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि क्रूरता, जो विवाह विच्छेद का आधार है, को जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक, को खतरा हो, या ऐसे खतरे की उचित आशंका पैदा हो। मानसिक क्रूरता के प्रश्न पर उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों, उनके सामाजिक मूल्यों, स्थिति और उनके रहने के वातावरण के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। क्रूरता में मानसिक क्रूरता भी शामिल है, जो वैवाहिक गलत व्यवहार के दायरे में आती है। क्रूरता शारीरिक होना आवश्यक नहीं है। यदि उसके पति/पत्नी के आचरण से यह स्थापित होता है और/या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पति/पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे दूसरे पति/पत्नी के मन में उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आशंका उत्पन्न होती है, तो यह आचरण क्रूरता माना जाएगा।

38. **ए. जयचंद्र** मामले (उपरोक्त) के पैरा 12 में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि क्रूरता माने जाने के लिए, शिकायत किया गया आचरण "गंभीर और वजनदार" होना चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि याचिकाकर्ता पति/पत्नी से दूसरे पति/पत्नी के साथ रहने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह "विवाहित जीवन की सामान्य टूट-फूट"

से कहीं अधिक गंभीर होना चाहिए। परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, आचरण की जाँच इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए की जानी चाहिए कि क्या शिकायत किया गया आचरण वैवाहिक कानून में क्रूरता माना जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आचरण पर कई कारकों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए जैसे कि पक्षों की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ, रीति-रिवाज और परंपराएँ। क्रूरता की परिभाषा निर्धारित करना या उन परिस्थितियों का विस्तृत विवरण देना कठिन है जो क्रूरता का गठन करेंगी। यह इस प्रकार का होना चाहिए कि न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करे कि दूसरे पति या पत्नी के आचरण के कारण दोनों पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि उनके लिए मानसिक पीड़ा, यातना या संकट के बिना साथ रहना असंभव हो गया है, ताकि शिकायतकर्ता पति या पत्नी तलाक प्राप्त करने का हकदार हो सके। क्रूरता के लिए शारीरिक हिंसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है और अथाह मानसिक पीड़ा और यातना देने वाला आचरण अधिनियम की धारा 10 के अर्थ में क्रूरता माना जा सकता है। मानसिक क्रूरता में गंदी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके मौखिक गालियाँ और अपमान शामिल हो सकते हैं, जिससे दूसरे पक्ष की मानसिक शांति लगातार भंग होती है।

39. ए. जयचंद्र मामले (उपरोक्त) के पैरा 13 में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि उसके समक्ष समस्याएँ मानव की हैं और तलाक की याचिका का निपटारा करने से पहले पति/पत्नी के आचरण में आए मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। चाहे वह कितना भी तुच्छ या मामूली क्यों न हो, ऐसा आचरण दूसरे के मन में पीड़ा पैदा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि ऐसे आचरण को क्रूरता कहा जा सके, उसे एक निश्चित गंभीरता तक पहुँचना होगा। इसकी गंभीरता का आकलन करना न्यायालय का काम है। यह देखना होगा कि क्या आचरण ऐसा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी विचार करना होगा कि क्या शिकायतकर्ता को सामान्य मानव जीवन के एक हिस्से के रूप में सहन करने के लिए कहा जाना चाहिए।

प्रत्येक वैवाहिक आचरण, जो दूसरे को परेशान कर सकता है, क्रूरता नहीं माना जा सकता। केवल मामूली चिड़चिड़ाहट, झगड़े, जो दैनिक विवाहित जीवन में होते हैं, भी क्रूरता नहीं माने जा सकते। वैवाहिक जीवन में क्रूरता निराधार हो सकती है, जो सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है। यह शब्दों, इशारों या केवल मौन, हिंसक या अहिंसक हो सकती है।

40. **हरभजन सिंह मोंगा बनाम अमरजीत कौर** मामले में, जैसा कि 1985 एससीसी ऑनलाइन एमपी 83 में बताया गया है, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि दूसरे पति या पत्नी और उसके/उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में झूठा फंसाने के लिए आत्महत्या करने की धमकी भी क्रूरता मानी जाती है।

41. **श्रीमती उमा वंती बनाम अर्जन देव** मामले में, जैसा कि 1995 एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच 56 में बताया गया है, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा पति या पत्नी का अजीबोगरीब व्यवहार भी क्रूरता माना जाता है। माननीय न्यायालय ने माना था कि अपीलकर्ता का दिन-प्रतिदिन का व्यवहार ऐसा था जिससे प्रतिवादी की मानसिक शांति और सद्भाव भंग होता था, जो निश्चित रूप से कानूनी क्रूरता माना जाता था। हो सकता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, लेकिन प्रतिवादी द्वारा साबित किए गए उसके अजीबोगरीब व्यवहार कानूनी क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त हैं। पति अपीलकर्ता के साथ शांति से नहीं रह सकता था। उसके अजीबोगरीब व्यवहार के कारण शांति हमेशा भंग होती थी, और इसलिए उसे इस बात पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि उसका व्यवहार उसके प्रति क्रूर था।

42. **श्रीमती रीता निझावन बनाम श्री बाल कृष्ण निझावन**, जैसा कि आईएलआर (1973) 1 दिल्ली 944 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि नपुंसकता के कारण या किसी अन्य कारण से यौन संबंध बनाने से इनकार करना पीड़ित पति/पत्नी के प्रति क्रूरता है। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यौन संबंध विवाह का आधार है और एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण यौन गतिविधि के बिना किसी भी विवाह का लंबे समय तक चलना असंभव होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाह में यौन

गतिविधि का महिला के मन और शरीर पर अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि उसे उचित यौन संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह अवसाद और हताशा का कारण बनेगी। ऐसा कहा गया है कि सुखी और सामंजस्यपूर्ण यौन संबंध महिला के मस्तिष्क को जीवंत बनाते हैं, उसके चरित्र का विकास करते हैं और उसकी जीवन शक्ति को तीन गुना बढ़ा देते हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यौन संबंध में निराशा से अधिक घातक कुछ भी विवाह के लिए नहीं है।

43. माननीय न्यायालय ने श्रीमती रीता निझावन मामले (उपरोक्त) में आगे कहा कि कानून में यह सुस्थापित है कि यदि विवाह का कोई भी पक्ष स्वस्थ शारीरिक क्षमता वाला होने के बावजूद यौन संबंध बनाने से इनकार करता है, तो यह क्रूरता मानी जाएगी और दूसरे पक्ष को डिक्ली का हकदार बनाएगी। हमारी राय में, कानून में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यौन संबंध से इनकार प्रतिवादी की यौन कमजोरी का परिणाम है जो उसे अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थ बनाती है, या प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर इनकार करने के कारण है; ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही मामलों में परिणाम एक ही है, अर्थात् सामान्य यौन जीवन से इनकार के कारण अपीलकर्ता को निराशा और दुख और इसलिए क्रूरता।

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम के जया घोष पैरा 99 में ने (2007) 4 एससीसी 511 में अपनी रिपोर्ट में क्रूरता के मुद्दे पर कई निर्णयों का उल्लेख और चर्चा करने के बाद यह पाया है कि मानव मन अत्यंत जटिल है और मानव व्यवहार भी उतना ही जटिल है। इसी प्रकार, मानवीय सरलता की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए, संपूर्ण मानव व्यवहार को एक परिभाषा में समाहित करना लगभग असंभव है। एक मामले में जो क्रूरता है, वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं भी हो सकती है। क्रूरता की अवधारणा व्यक्ति के पालन-पोषण, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, मानवीय मूल्यों और उनकी मूल्य प्रणाली के आधार पर अलग-अलग होती है।

45. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **समर घोष** मामले (उपरोक्त) में आगे कहा है कि मानसिक क्रूरता की अवधारणा की कोई व्यापक परिभाषा नहीं हो सकती जिसके अंतर्गत मानसिक क्रूरता के सभी प्रकार के मामलों को शामिल किया जा सके। **माननीय न्यायालय** ने पैरा 100 में आगे कहा है कि मानसिक क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं रह सकती; यह समय के साथ, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मूल्य प्रणाली आदि के साथ बदलने के लिए बाध्य है। जो अभी मानसिक क्रूरता हो सकती है, वह समय बीतने के बाद मानसिक क्रूरता नहीं रह सकती है या इसके विपरीत। वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित सूत्र या निश्चित मानदंड कभी नहीं हो सकते। मामले का निर्णय करने का विवेकपूर्ण और उचित तरीका यह होगा कि उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाए।

46. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **समर घोष** मामले (उपरोक्त) के पैरा 101 में आगे कहा है कि मार्गदर्शन के लिए कभी भी कोई एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, माननीय न्यायालय ने मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझा जो "मानसिक क्रूरता" के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं, इस सावधानी के साथ कि ऐसे उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा उल्लिखित उदाहरण इस प्रकार हैं:

“(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट जो पक्षकारों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाते, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं।

ii) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का व्यापक मूल्यांकन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को ऐसे आचरण को सहन करने और दूसरे पक्षकार के साथ रहना जारी रखने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता।

iii) केवल ठंडापन या स्नेह की कमी क्रूरता नहीं हो सकती, भाषा में बार-बार अशिष्टता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा इस हद तक पहुँच सकती है कि यह दूसरे पति या पत्नी के लिए विवाहित जीवन को बिल्कुल असहनीय बना देती है।

iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। एक पति या पत्नी में लंबे समय तक दूसरे के आचरण के कारण गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

v) निरंतर पति/पत्नी के जीवन को यातना देने, असुविधा पहुँचाने या कष्टदायक बनाने के लिए अपमानजनक और अपमानजनक व्यवहार।

vi) एक पति/पत्नी का लगातार अनुचित आचरण और व्यवहार जो वास्तव में दूसरे पति/पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, ठोस और भारी होनी चाहिए।

vii) लगातार निंदनीय आचरण, जानबूझकर की गई उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है या परपीड़क सुख प्राप्त होता है, भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है।

viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकार-बोध से कहीं अधिक होना चाहिए, जिससे दुख और असंतोष और भावनात्मक परेशानी होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का आधार नहीं हो सकता।

ix) केवल मामूली चिड़चिड़ाहट, झगड़े, दैनिक जीवन में होने वाली सामान्य टूट-फूट, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

x) विवाहित जीवन की समग्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और कुछ वर्षों की अवधि में कुछ छिटपुट घटनाओं को क्रूरता नहीं माना जाएगा। दुर्व्यवहार काफी लंबे समय तक जारी रहना चाहिए, जहाँ रिश्ता इस हद तक बिगड़ गया हो कि पति/पत्नी के कार्यों

और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल हो रहा हो, तो यह मानसिक क्रूरता मानी जा सकती है।

xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सीय कारणों और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के, नसबंदी ऑपरेशन के लिए खुद को प्रस्तुत करता है और इसी प्रकार, यदि पत्नी बिना चिकित्सीय कारणों या अपने पति की सहमति या जानकारी के, नसबंदी या गर्भपात कराती है, तो पति/पत्नी का ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के, काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक का संतान न होने का एकतरफा निर्णय क्रूरता माना जा सकता है।

xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही हो, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार के परे है। विवाह एक काल्पनिक बंधन बन जाता है, हालाँकि यह एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। ऐसे मामलों में, उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके, कानून विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।”

47. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 2010 एससीसीआर 265 में वर्णित रवि कुमार बनाम जुमला देवी के पैरा 18 में, यह टिप्पणी की कि वैवाहिक संबंधों में, क्रूरता का स्पष्ट अर्थ पति-पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समझ का अभाव है, जो रिश्ते को कड़वा बनाता है और अक्सर व्यवहार के विभिन्न विस्फोटों को जन्म देता है जिन्हें क्रूरता कहा जा सकता है। वैवाहिक संबंधों में कभी-कभी क्रूरता हिंसा का रूप ले सकती है, कभी-कभी यह एक अलग रूप भी ले सकती है। कभी-कभी, यह केवल एक रवैया या दृष्टिकोण हो सकता है। कुछ स्थितियों में चुप्पी क्रूरता के समान हो सकती है। इसलिए, वैवाहिक व्यवहार में क्रूरता किसी भी परिभाषा को चुनौती देती है और इसकी श्रेणी को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। पति अपनी पत्नी के

प्रति क्रूर है या पत्नी अपने पति के प्रति क्रूर है, इसका पता और निर्णय दिए गए मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, न कि किसी पूर्व-निर्धारित कठोर सूत्र द्वारा। क्रूरता वैवाहिक मामले अनगिनत प्रकार के हो सकते हैं। यह सूक्ष्म भी हो सकता है या क्रूर भी हो सकता है और हावभाव और शब्दों से भी हो सकता है।

48. **रामचंदर बनाम अनंत** के पैरा 10 में, जैसा कि 2015(11)एससीसी 539 में रिपोर्ट किया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने यह टिप्पणी की है कि धारा 13(1)(आई-ए) के प्रयोजनों के लिए क्रूरता को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति व्यवहार के रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे दूसरे के मन में यह उचित आशंका उत्पन्न होती है कि उसके लिए दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखना सुरक्षित नहीं है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है।

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामचंदर मामले (उपरोक्त) में आगे यह भी कहा है कि क्रूरता के उदाहरणों को अलग-थलग नहीं लिया जाना चाहिए। यह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव है जिसे एक उचित निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या वादी ने दूसरे पति/पत्नी के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है।

50. **विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित** मामले में, जैसा कि (2006) 3 एससीसी 778 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 31 में यह माना है कि कई निर्णयों द्वारा यह तय होता है कि मानसिक क्रूरता शारीरिक क्षति से भी अधिक गंभीर चोट पहुँचा सकती है और घायल अपीलकर्ता के मन में ऐसी आशंका पैदा कर सकती है जैसा कि इस धारा में परिकल्पित है। इसका निर्धारण मामले के संपूर्ण तथ्यों और पति/पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया जाना है। क्रूरता माने जाने के लिए, पक्ष के साथ ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार होना चाहिए जिससे शरीर या मन को वास्तविक तथ्य के रूप में या आशंका के रूप में पीड़ा हुई हो इस तरह से कि पति/पत्नी का साथ रहना मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हानिकारक या क्षतिपूर्ण हो।

51. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता सक्सेना मामले** (उपरोक्त) के पैरा-32 में आगे यह भी कहा है मामले में कहा गया है कि "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसका प्रयोग मानव आचरण या मानवीय व्यवहार के संबंध में किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में या उनके संबंध में किया गया आचरण है। यह एक आचरण है और ऐसा आचरण है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ शिकायत किया गया आचरण स्वयं ही काफी बुरा और स्वयं में गैरकानूनी या अवैध है। तब दूसरे पति/पत्नी पर पड़ने वाले प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जाँच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, क्रूरता तभी स्थापित होगी जब आचरण स्वयं सिद्ध हो या स्वीकार किया गया हो।

52. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता सक्सेना मामले** (उपरोक्त) के पैरा-36 में आगे कहा है कि क्रूरता की कानूनी अवधारणा, जिसे कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, को सामान्यतः ऐसे आचरण के रूप में वर्णित किया जाता है जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) को खतरा हो या ऐसे खतरे की उचित आशंका पैदा करने के लिए। क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि पूरे वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, यह नियम तब विशेष महत्व रखता है जब क्रूरता हिंसक कृत्य न होकर हानिकारक निन्दा, शिकायतें, आरोप या ताने हों। यह मानसिक हो सकता है, जैसे पत्नी के प्रति उदासीनता और उदासीनता, उसे साथ देने से इनकार, पत्नी के प्रति घृणा या घृणा, या शारीरिक, जैसे हिंसा के कृत्य और बिना किसी उचित कारण के यौन संबंध से परहेज। यह साबित किया जाना चाहिए कि विवाह में एक साथी, चाहे वह परिणामों की परवाह किए बिना ही क्यों न हो, ने ऐसा व्यवहार किया है जिसे दूसरे पति या पत्नी को उन परिस्थितियों में सहन नहीं करना चाहिए था, और उस दुर्व्यवहार ने स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है या ऐसी चोट की उचित आशंका पैदा की है। क्रूरता के मामले में दो पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से, क्या इस अपीलकर्ता को क्या उन्हें इस आचरण को सहने के लिए कहा जा सकता है? प्रतिवादी की ओर से, क्या यह आचरण क्षम्य था? इसके बाद अदालत को यह तय करना होगा कि क्या

निंदनीय आचरण का कुल योग क्रूर था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संचयी आचरण इतना गंभीर था कि एक विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह कहा जा सके कि प्रतिवादी के पास परिस्थितियों में मौजूद किसी भी बहाने पर विचार करने के बाद, आचरण ऐसा है कि याचिकाकर्ता को सहन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

53. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता सक्सेना मामले** (उपरोक्त) के पैरा-37 में आगे कहा है कि उक्त प्रावधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित मानसिक क्रूरता क्या है, यह ऐसी घटनाओं की संख्यात्मक गणना या केवल ऐसे आचरण के निरंतर क्रम पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वास्तव में इसकी तीव्रता, गंभीरता और कलंकात्मक प्रभाव पर निर्भर करेगा, जब यह एक बार भी किया जाए और मानसिक दृष्टिकोण पर इसके हानिकारक प्रभाव पर, जो एक अनुकूल वैवाहिक घर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

54. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता सक्सेना मामले** (उपरोक्त) के पैरा-38 में आगे कहा है कि यदि ताने, शिकायतें और तिरस्कार केवल सामान्य प्रकृति के हैं, तो न्यायालय को शायद इस प्रश्न पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उनका जारी रहना या लंबे समय तक बने रहना, सामान्यतः इतना गंभीर कार्य नहीं है जो इतना हानिकारक और पीड़ादायक हो कि आरोपित पति/पत्नी वास्तव में और उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकें कि वैवाहिक घर का रखरखाव अब संभव नहीं है।

55. अब, **वर्तमान मामले पर आते हुए**, हम पाते हैं कि, बेशक, दोनों पक्षों का विवाह 10.07.1987 को हुआ था और विवाहेतर संबंध से दो पुत्रों का जन्म हुआ। पहला पुत्र, नरेंद्र भारती, 16.05.1991 को और दूसरा पुत्र, आदित्य कुमार, 15.08.1998 को हुआ था। आरोप के अनुसार, दूसरे बेटे के जन्म के बाद अपीलकर्ता/प्रतिवादी-पत्नी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया और इसलिए, 29.07.2008 को तलाक की याचिका दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता/प्रतिवादी-पत्नी द्वारा पति/वादी के खिलाफ की गई क्रूरता के रूप में दावा किए गए निम्नलिखित तथ्यों का हवाला दिया गया:

i) अपीलकर्ता/पत्नी उसके लिए खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी और वह हमेशा उससे झगड़ा करती थी और उसे घर की ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर करती थी और पत्नी भूतल पर रहती थी और दोनों का आपस में कोई लेना-देना नहीं था।

ii) पत्नी हमेशा उसे उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की धमकी देती थी।

(iii) उसने उसके खेत से गेहूं, चावल और अन्य अनाज बेचे और उसकी पीठ पीछे महंगे बर्तन और गहने भी बेचे।

(iv) पत्नी ने असामाजिक तत्वों की मदद से उसे जान से मारने की धमकी दी।

(v) कई बार, पति गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसे भरावपर स्थित प्रशांत क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन पत्नी कभी उससे मिलने नहीं आई।

56. प्रतिवादी/पत्नी ने अपने लिखित बयान में याचिका में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और जोरदार दलील दी है कि पति बीमा व्यवसाय में एक एजेंट है और आरएसएस और भाजपा का सक्रिय सदस्य है और परिणामस्वरूप उसने कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ अंतरंगता विकसित की, जिनमें से एक राजगीर की है। उसने आगे दलील दी है कि राजगीर की महिला को उसका पति अक्सर अपने घर ले जाता था और अपीलकर्ता/प्रतिवादी पत्नी द्वारा आपत्ति जताए जाने पर, उसका पति उसे पीटता था। उसने यह भी दलील दी है कि पति उसके प्रति उदासीन हो गया और उसने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया। हालाँकि, जब भी वह उसके पास आया, उसने उसका स्वागत किया और यह कहना गलत है कि पिछले दस वर्षों से कोई सहवास नहीं है। उसने आगे दलील दी है कि वह उस महिला का नाम नहीं जानती जिसके साथ उसके पति के अंतरंग संबंध हैं, लेकिन वह उसका चेहरा जानती है। उसने यह भी दावा किया है कि तलाक की याचिका राजगीर की महिला से शादी करने के इरादे से दायर की गई है। उसने आगे कहा है कि वह एक पर्दानशी महिला है और मंदिर में पूजा करने के अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं जाती। उसने यह भी कहा है कि वह हमेशा उसके साथ रहने को तैयार है

और सच तो यह है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध के कारण उससे छुटकारा पाना चाहता है। यह भी कहा गया है कि पति खुद घर की दूसरी मंजिल पर चला गया और अपनी पत्नी और बेटों को उस मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं दी जहाँ वह रहता था और वह अक्सर घर से बाहर रहता है और जब भी आता है देर रात आता है।

57. वादी/पति, जो इस मामले में प्रतिवादी है, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि तलाक की याचिका के समर्थन में, उसके सहित पाँच गवाहों से पूछताछ की गई है।

58. अ.सा.-1 - दिलीप कुमार सिंह से 14.07.2009 को पूछताछ की गई और हमने पाया कि जिरह में, उसने यह बयान दिया है कि वह आठ साल पहले वादी/प्रतिवादी के घर गया था और वह कई बार उसके घर गया था। यहाँ, यह बताना प्रासंगिक है कि तलाक की याचिका के अनुसार, 1999 से ही विवाह में खटास आ रही थी, लेकिन इस दावे के अनुसार कि वह आठ साल पहले वादी के घर गया था, इसका मतलब है कि वह वर्ष 2001 में गया था। इस प्रकार, वह यह कहने की स्थिति में नहीं है कि 2001 से पहले दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ था। वैसे भी, यह गवाह बाहरी व्यक्ति है और अपीलकर्ता प्रतिवादी-पत्नी एक पर्दानशीन महिला है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस गवाह के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी के साथ बातचीत करने का कोई अवसर नहीं है और वह अपीलकर्ता-प्रतिवादी की प्रकृति के बारे में कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी और उसके पारिवारिक मामलों की प्रकृति के बारे में उसके साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।

59. अ.सा.-2 - पारसनाथ की 15.02.2010 को परीक्षा की गई। वह भी एक बाहरी व्यक्ति है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी, जो एक पर्दानशीन महिला है, के पारिवारिक मामलों को देखने का भी शायद ही कोई अवसर मिला हो। जिरह के दौरान दिए गए उसके बयान के मद्देनज़र उसका साक्ष्य खारिज किए जाने योग्य है, जिसके अनुसार, उसे यह भी नहीं पता कि पक्षकार अपने-अपने घर में रह रहे थे या नहीं, न ही वह विवाह के पक्षकारों के आस-पास के घरों में रहने वाले लोगों के नाम जानता था। उसे यह भी नहीं पता था कि पक्षकार अलग-अलग रहते हैं या नहीं।

60. अ.सा.-3- परशुराम कुमार से 24.02.2010 को पूछताछ की गई। अपनी जिरह में उसने यह गवाही दी है कि प्रतिवादी/वादी की माँ अपने दूसरे बेटे शिवरतन प्रसाद गुप्ता के साथ उससे अलग रह रही है। उसने अपनी जिरह में यह भी गवाही दी है कि प्रतिवादी/वादी-पति वर्तमान में अपने घर से दूर रह रहा है और वह पिछले पाँच वर्षों से घर नहीं जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच पति-पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है।

61. अ.सा.-4- विनोद कुमार से 15.03.2010 को पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि प्रतिवादी/वादी आरएसएस का सदस्य है और वर्तमान में वह आरएसएस के कार्यालय में रह रहा है।

62. वादी/प्रतिवादी ने स्वयं को अ.सा.-5 के रूप में पेश किया है। उन्होंने अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि पत्नी अभी भी बच्चों के साथ उनके घर में रह रही है। हालाँकि, वह उनके साथ नहीं रहते और आरएसएस कार्यालय में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि लगभग दस वर्षों से उनकी पत्नी से बातचीत नहीं हो रही है, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2000 से उनकी पत्नी से बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि उनसे 26.03.2010 को पूछताछ की गई थी।

63. अपीलकर्ता/प्रतिवादी-पत्नी से व.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई है और अपनी जिरह में उसने यह बयान दिया है कि उसके पति के साथ उसके संबंध 2006 तक अच्छे थे। उसने यह भी बयान दिया है कि वह अपने बच्चों के साथ अपने वैवाहिक घर में रह रही है और उसका पति उसके साथ नहीं रह रहा है। उसने यह भी बयान दिया है कि वह उस महिला का नाम नहीं जानती जिसके साथ उसके पति का अवैध संबंध है, लेकिन वह उसे चेहरे से पहचान सकती है।

64. व.सा.-2 - सुरेश प्रसाद गुप्ता और व.सा.-3 - अशोक कुमार ने अपनी गवाही के दौरान कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं दिया है।

65. व.सा.-4 - आदित्य कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है, क्योंकि वह अपीलकर्ता और प्रतिवादी का छोटा बेटा है। अपनी जिरह में उसने यह बयान दिया है कि 2006 से पहले उसके माता और पिता के बीच संबंध अच्छे थे। उसने आगे यह भी गवाही दी है कि उसके पिता

उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहते और वह उसे पीटते भी थे और यहाँ तक कि उसे बिजली का करंट भी लगाते थे।

66. उपरोक्त साक्ष्यों से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी-वादी पति के साक्ष्य के अनुसार, 1999 से ही विवाह में खटास आने लगी थी, लेकिन तलाक की याचिका नौ साल के लंबे अंतराल के बाद, वर्ष 2008 में दायर की गई थी। यदि पत्नी की ओर से की गई कथित क्रूरता सच थी, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी-वादी-पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर करने के लिए नौ साल तक इंतजार क्यों किया। यह परिस्थिति उसके खिलाफ जाती है जिससे अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी द्वारा कथित रूप से की गई क्रूरता का उसका दावा अविश्वसनीय हो जाता है। इसके अलावा, व.सा.-4, जो पक्षकारों का पुत्र है, का साक्ष्य कि 2006 तक, उसके माता और पिता के बीच संबंध अच्छे थे और उसके पिता उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहते थे और वह उन्हें पीटते थे और यहाँ तक कि उन्हें बिजली का करंट भी लगाते थे, वादी/प्रतिवादी के मामले को और भी अविश्वसनीय बनाता है।

67. इस साक्ष्य के मद्देनजर कि पति और पत्नी के बीच संबंध वर्ष 2006 से पहले अच्छे थे, पति का यह मामला कि 1999 से पत्नी/अपीलकर्ता उससे झगड़ा करती थी और उसके लिए खाना बनाने को तैयार नहीं थी, ज़मीन पर गिर जाता है।

68. हम आगे पाते हैं कि दोनों पक्षों के साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी अभी भी अपने बच्चों के साथ अपने वैवाहिक घर में रह रही है और पति ही है, जो अपना घर छोड़कर आरएसएस के कार्यालय में रह रहा है। हम यह भी पाते हैं कि पत्नी ने कभी भी सहवास से इनकार नहीं किया है, पति ने ही उसमें रुचि लेना बंद कर दिया है और वह सहवास के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि वह उससे अलग रह रहा है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी ने हमेशा यह कहा है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और जब भी वह घर आता है, वह हमेशा उसका स्वागत करती है और उसने कभी भी सहवास से इनकार नहीं किया है। उसने यह भी गवाही दी है कि यह कहना गलत है कि 2008 में तलाक की याचिका दायर करने से पहले, पति और पत्नी के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि पति को अपनी

पत्नी की कोई चिंता नहीं है, न कि पत्नी को अपने पति की। साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि प्रतिवादी/पति की माँ उससे अलग रहती है क्योंकि वह अपने दूसरे बेटे के साथ रहती है। ऐसे में, पत्नी/अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

69. इस आरोप के संबंध में कि पत्नी अपने पति को आपराधिक मामला दर्ज कराने की धमकी देती थी, हम पाते हैं कि रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत नहीं है और यदि किसी के खिलाफ कोई अपराध किया भी जाता है, तो भी पीड़िता को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार है और साक्ष्य के अनुसार, हम पाते हैं कि प्रतिवादी-वादी-पति अपनी पत्नी को तब पीटता था जब वह किसी अन्य महिला के साथ उसके अवैध संबंध का विरोध करती थी। यहाँ तक कि पक्षकारों के पुत्र, जिसकी डी.डब्ल्यू.-4 के रूप में जाँच की गई है, ने भी गवाही दी है कि उसके पिता उसकी माँ को पीटते थे और यहाँ तक कि उन्हें बिजली का करंट भी लगाते थे। इस प्रकार, कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की धमकी को क्रूरता नहीं माना जा सकता। यह भी बताना उचित है कि पति/वादी का मामला यह नहीं है कि प्रतिवादी/पत्नी ने झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी या उसने कोई झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराया है।

70. जहाँ तक अपीलकर्ता/प्रतिवादी-पत्नी द्वारा गेहूँ, चावल और अन्य अनाज, बर्तन और आभूषण बेचने के आरोप का संबंध है, हम पाते हैं कि इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। अन्यथा भी, ऐसी गतिविधि को पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। अनाज और आभूषण बेचना क्रूरता नहीं माना जा सकता।

71. जहाँ तक इस आरोप का संबंध है कि पत्नी ने अपने पति को असामाजिक तत्वों की मदद से जान से मारने की धमकी दी, इस आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी एक पर्दानशीन महिला है और स्पष्ट रूप से उसका किसी भी असामाजिक तत्व या अपराधी से कोई संपर्क नहीं हो सकता। वैसे भी, इस तरह की धमकी की तारीख और स्थान के संदर्भ में कोई विशिष्ट उदाहरण उसके साक्ष्य में नहीं दिया गया है। जहाँ तक प्रतिवादी-वादी-पति के इस आरोप का संबंध है कि वह कई बार बीमार पड़ा और

भाराओपर स्थित प्रशांत क्लिनिक में भर्ती हुआ, लेकिन पत्नी कभी उससे मिलने नहीं आई, तो हम पाते हैं कि इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। प्रतिवादी-वादी-पति ने अपनी बीमारी की तारीख और प्रकृति और अस्पताल में भर्ती होने के समय के बारे में कोई दलील या गवाही नहीं दी है। उसने यह भी साबित नहीं किया है कि उसकी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में पता था और वह उससे मिलने नहीं आई।

72. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की समग्रता में, हम पाते हैं कि प्रतिवादी वादी-पति द्वारा ऐसा कोई उदाहरण सिद्ध नहीं किया गया है, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दिए गए सख्त अर्थ में क्रूरता माना जा सके, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अधिनियम के तहत क्रूरता का क्या अर्थ है। पति/वादी, जो यहाँ प्रतिवादी है, अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से ऐसा कोई कदाचार साबित करने में विफल रहा है जिसे गंभीर और महत्वपूर्ण माना जा सके और जिससे उसे ऐसे किसी खतरे की उचित आशंका हो जो उसके लिए अपीलकर्ता पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना असुरक्षित बना दे। हो सकता है कि दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन में सामान्य टूट-फूट हुई हो, लेकिन निश्चित रूप से अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा पति/प्रतिवादी के प्रति कोई क्रूरता नहीं की गई है। वास्तव में, क्रूरता विपरीत तरीके से की गई प्रतीत होती है। अतः, यह बिन्दु प्रतिवादी-वादी के विरुद्ध और अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

बिन्दु संख्या 2

73. बिन्दु संख्या 1 के संबंध में निष्कर्ष के आलोक में, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी-वादी-पति अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि वह अपीलकर्ता-प्रतिवादी-पत्नी के विरुद्ध तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए क्रूरता का आधार साबित करने में विफल रहा है।

74. उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, हमारा यह सुविचारित मत है कि विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। अतः, वर्तमान विविध अपील को स्वीकार किया जाता है और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा तलाक वाद

संख्या 72/2008 में पारित दिनांक 07.10.2017 के विवादित निर्णय को अपास्त किया जाता है। हालाँकि, दोनों पक्ष अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

75. रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति पारिवारिक न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों के बीच प्रसारित करें और एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को भेजें।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

अमरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।